12. Vishwa Bharati Spinning & Weaving Cooperative Society Ltd., Bhiwandi.
13. Yeotmal Ziala Sahakari Soot Wa Kapad Girni Ltd., Pusad.
14. The Yeshwant Sahakari Soot Girni Niyamit, Bhor.
15. The Yeshwant Sahakari Soot Girni Niyamit, Solapur.
16. The Jawahar Sahakari Kapus Utpadak Soot Girni Maryadit, Latur.

Increase in import duty on Life Saving Drug (Erthromycine)

1072. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the import duty on TIOC intermediate for life saving drug Erythromycine has been increased lately from 25 per cent to 145 per cent; and

(b) if so, whether Government propose to reduce it to ease the hardships caused to common man?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) The import duty on TIOC has been increased from 125 per cent plus Rs. 25 per kg. to 145 per cent *ad-valorem* with effect from the 16th December, 1988.

(b) Erythromycin is an item covered by the Drugs (Price Control) Order, 1987. There is no proposal at present to reduce the duty on TIOC.

"रूरल बैंक्स इन बैड शेप स्टडी" शीर्षक नामक समाचार

1073. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23.11.88 के फ्रायनेंशियल एक्सप्रैस में "रूरल बैंक्स इन बैड शेप स्टडी" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋण के वितरण को सरल बनाने के लिए कई उपाए किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :– छोटे किसानों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सरल आवेदन प्रपत्र, ऋण आवेदन के निपटान के लिए समय सीमा का निर्धारण कमजोर वर्गों के उधारकर्ताओं की सहायता के लिए शाखा प्रबन्धकों को आवश्यक शक्तियां, अन्य पक्षीय गारन्टी के लिए जोर न देना, ऋणों के संवितरण के लिए निश्चित कार्य दिन निर्धारित करना और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन दिनों आकस्मिक जांच करना, सप्ताह में एक दिन गैर-सरकारी कारबार दिवस के रूप में मनाना।

बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई ऋण धनराशि

1074. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संबद्ध व्यक्तियों से ऋणों की वसूली न होने की वजह से, देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की भारी राशियों को प्रतिवर्ष बट्टे खाते में डाल दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन धनराशियों का ब्यौरा क्या है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार बट्टे खाते में डाली गई; और

(ग) ऐसे ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में मानदण्ड क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडूवर्डो फेलेरियो): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं तथा रीति-रिवाजों के अनुसार एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित लाभ-हानि विवरण के प्रपत्रों के अनुसार, जिनका सभी बैंकों को पालन करना होता है, बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों तथा बट्टे खाते डाली गयी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की रकम प्रकट करने से सांविधिक सुरक्षा प्राप्त हैं जिनके लिये उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था की जाती है।

बैंक अपने ऋणों की रकमें वसूल करने के लिये कई उपाय करते हैं जैसे प्रतिभूतियों की वसूली और बिक्री और यथाउपलब्ध गारंटियों को लागू करना और यथाउपलब्ध बीमा कवच से वसूली करना। बैंक अपने ऋणों की वसूली के लिये दीवानी मुकदमें भी दायर करते हैं। बैंक अशोध्य ऋणों के रूप में रकमें तभी बट्टे खाते डालते हैं जब उनकी वसूली के सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं।

Supply of Cheaper Diesel Fuel to Fishing Industry

1075. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether MPEDA has submitted a proposal to arrange for cheaper diesel fuel to fishing industry;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when this proposal is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) to (c) A scheme was notified in July, 1988 for providing supply of diesel oil at special prices comparable to international prices to eligible production units exporting 25 per cent or more of their production for their captive power generation subject to certain conditions. The Marine Products Export Development Authority have recently suggested a scheme to the Government for expanding the scope of the present scheme to cover supply of diesel oil at international price for deep sea fishing vessel operations. There is no proposal to accept the scheme suggested by MPEDA.

Procurement of Iron Ore from Orissa

1076. SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the procurement of iron Ore by MMTC from Barbil, Banspani and Barjomda sectors in Orissa has declined during the year 1987-88 and in 1988-89;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps are proposed to be taken to increase the procurement of iron ore from these sectors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) Yes, Sir.

(b) Inspite of unfavourable loading conditions for ships at Paradip Port, procurement poilcy of MMTC for